

(b) if so, the facts thereof; and

(c) what effective measures are proposed to be taken to put an end to this menace?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Customs Department has the requisite arrangements and expertise for checking the correctness of export values. Although there have been some cases where under-valuation of exports has been detected by the Calcutta Custom House in the past few years and these cases have been dealt with under the law, there is nothing to indicate that crores of rupees in foreign exchange have been lost as a result of continued under-invoicing of exports from Calcutta.

Effect of Import Policy on Industry

2925. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the new import policy has not helped the growth of Industry in the country to its expectations;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any modifications are being considered?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) to (c). It is too early to assess the impact of new Import Policy on the growth of the industry. Besides, import policy is one of the various elements of the industrial development strategy. An evaluation of the import policy will be undertaken in due course when the modifications, which appear necessary in the light of experience, will be considered.

राज्य व्यापार निगम द्वारा इंजीनियरिंग फर्मों को आयातित सामग्री उपलब्ध कराना

2926. श्री मोठा लाल पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम समय पर इंजीनियरिंग फर्मों को अपेक्षित आयातित सामग्री उपलब्ध नहीं कर पाती और क्या फर्मों ने यह मांग की है कि उन्हें स्वयं ही सीधे आयात की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग के बारे में राज्य व्यापार निगम अथवा सरकार को क्या आपत्ति है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम इंजीनियरिंग फर्मों को कच्चे माल की सप्लाई करने का कार्य नहीं करता। परन्तु राज्य व्यापार निगम का एक अनुषंगी निकाय राज्य रसायन और औषधि निगम इंजीनियरिंग एवं धातुकर्मी उद्योगों को कतिपय रासायनिक मर्दे सप्लाई करता है। आयात नीति से ऐसे आवश्यक उपबन्ध हैं कि जब कभी कोई मार्गीकरण अभिकरण क्रमिक सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार, जो आपस में तय हो, अथवा पंजीकरण की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, कच्चे माल की सप्लाई का प्रबन्ध करने की स्थिति में हो, तो वास्तविक उपभोक्ता सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अपेक्षित कच्चे माल के सीधे आयात की अनुमति देने के लिए अनुरोध कर सकता है।